The ACHIEVERS IAS ACADEMY

The ACHIEVERS IAS ACADEMY

PATNA

Daily NEWS CHRONICLE

IDEAL FOR

For UPSC/BPSC & For other Exams

Hindi

NEWS CREDIT

PIB/ PTI/ News On Air/ The Hindu/ IANS/ Business Standard/ Times Of India/ Deccan Herald/ Hindustan Times/ BBC News/ Aljazeera/ Mirror.Uk/ Times Now/ Economic Times/ Financial Express/ Indian Express...

NEWS COVERED

Business News, financial news, economy news, company news, politics news, India news, breaking news, Indian economy, International News, Sports News, and many more topics...

Saturday, July 25, 2026

+91 8434931877 www.achieversiaspatna.co.in achieversiaspatna@gmail.com

दिन की प्रमुख घटनाएं

- भारत ने 350 किलोग्राम का स्वदेशी थ्रस्ट टर्बोजेट इंजन विकसित किया, रक्षा प्रौद्योगिकी को आत्मनिर्भरता को आगे बढ़ाया
- रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने वायु रक्षा को मजबूत करते हुए सतह से हवा में मार करने वाली लंबी दूरी की स्वदेशी मिसाइल 'कुश' का सफल परीक्षण किया
- भारत और रोमानिया ने विज्ञान, शिक्षा और खेल सहयोग बढ़ाने के लिए तीन समझौतों पर हस्ताक्षर किए
- एसीसी ने प्रमुख नौकरशाही फेरबदल को मंजूरी दी, 13 वरिष्ठ अधिकारियों को नए सचिव नियुक्त किए
- इंफोसिस ने आशीष कुमार दास को 2027 से सीईओ और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया
- राजनाथ सिंह ने वैश्विक यात्रा के बाद पहली महिला तीनों सेनाओं के अभियान 'समुद्र प्रदक्षिणा' में शामिल होने के लिए झंडी दिखाई
- अमेरिका ने जबरन श्रम प्रवर्तन मुद्दों पर भारतीय सामानों पर अतिरिक्त 10% टैरिफ लगाया
- NPCI का UPI मेटा फ्रेमवर्क छोटी फिनटेक कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा की चिंताओं को बढ़ाता है
- केंद्रीय केवाईसी प्रणाली एकमुश्त ग्राहक सत्यापन प्रक्रिया के माध्यम से बैंकिंग सेवाओं को सरल बनाती है
- वैभव सूर्यवंशी ने अंतरराष्ट्रीय अर्धशतक बनाने वाले सबसे कम उम्र के क्रिकेटर के रूप में बनाया रिकॉर्ड

The ACHIEVERS IAS ACADEMY

भारत ने 350 किलोग्राम थ्रस्ट क्लास में पहला स्वदेशी एक्सपेंडेबल टर्बोजेट इंजन विकसित किया

- भारत ने 350 किलोग्राम थ्रस्ट क्लास में अपने पहले स्वदेशी एक्सपेंडेबल टर्बोजेट इंजन (ETJE) के सफल विकास के साथ स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकी में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है।
- इंजन को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) की एक प्रयोगशाला, गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट (जीटीआरई) द्वारा डिजाइन किया गया है, और आजाद इंजीनियरिंग लिमिटेड, हैदराबाद द्वारा निर्मित और असेंबल किया गया है। यह सफलता आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत उन्नत एयरो-इंजन प्रौद्योगिकी में भारत की आत्मनिर्भरता को महत्वपूर्ण रूप से मजबूत करती है।

कार्यक्रम के उद्देश्य:

- स्वदेशी एयरो-इंजन क्षमता विकसित करना।
- आयातित प्रणोदन प्रणालियों पर निर्भरता कम करें।
- स्वदेशी मिसाइल और यूएवी कार्यक्रमों का समर्थन करना।
- भारत के रक्षा औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना।
- रणनीतिक प्रौद्योगिकियों में सार्वजनिक-निजी सहयोग को बढ़ावा देना।

एक्सपेंडेबल टर्बोजेट इंजन क्या है?

- एक्सपेंडेबल टर्बोजेट इंजन (ETJE) एक कॉम्पैक्ट जेट इंजन है जिसे मुख्य रूप से एक बार उपयोग किए जाने वाले हवाई प्लेटफार्मों के लिए डिज़ाइन किया गया है।

प्रमुख अनुप्रयोग

• क्रूज मिसाइलें।
• घूमने वाले युद्ध सामग्री।
• लक्ष्य ड्रोन।
• लंबी दूरी के यूएवी।
• डिकॉय सिस्टम।

- पुन: प्रयोज्य विमान इंजनों के विपरीत, व्यय योग्य टर्बोजेट इंजन लागत प्रभावी, उच्च गति, लंबी दूरी के मिशनों के लिए अनुकूलित हैं।

टर्बोजेट इंजन क्या है?

- टर्बोजेट एक गैस टरबाइन इंजन है जो हवा को संपीड़ित करके, इसे ईंधन के साथ मिलाकर, मिश्रण को जलाकर और उच्च गति वाली निकास गैसों को बाहर निकालकर जोर उत्पन्न करता है।

काम के सिद्धांत:

• हवा का सेवन।
• कंप्रेसर।
• दहन कक्ष।
• टरबाइन।
• निकास नोजल।

विमान के इंजन के प्रकार:

• इंजन का प्रकार:	प्रमुख अनुप्रयोग
• टर्बोजेट	मिसाइलें, उच्च गति वाले विमान
• टर्बोफैन	वाणिज्यिक और लड़ाकू विमान
• टर्बोप्रॉप	क्षेत्रीय विमान
• टर्बोशाफ्ट	हेलीकाप्टर
• रैमजेट	सुपरसोनिक मिसाइलें
• स्क्रैमजेट	हाइपरसोनिक वाहन

DRDO के बारे में:

• स्थापित:1958
• मुख्यालय: नई दिल्ली
• चेयरमैन: राजेश कुमार सिंह
• आदर्श वाक्य: "बालस्य मूलम विज्ञानम" (शक्ति की उत्पत्ति विज्ञान है)

गैस टरबाइन अनुसंधान प्रतिष्ठान (GTRE):

• मूल संगठन: DRDO
• स्थान: बेंगलुरु, कर्नाटक
• निदेशक: डॉ. एस वी रमण मूर्ति
• विशेषज्ञता: एयरो-इंजन अनुसंधान और गैस टरबाइन प्रौद्योगिकी

प्रमुख परियोजनाएं:

- कावेरी इंजन कार्यक्रम।
- स्वदेशी गैस टरबाइन इंजन।
- उन्नत प्रणोदन प्रणाली।
- सैन्य प्लेटफार्मों के लिए एयरो-इंजन तकनीक।

आजाद इंजीनियरिंग लिमिटेड के बारे में:

• मुख्यालय: हैदराबाद, तेलंगाना
• क्षेत्र: सटीक इंजीनियरिंग
• विशेषज्ञता: एयरोस्पेस, रक्षा, ऊर्जा और तेल और गैस घटक

भूमिका:

- स्वदेशी खर्च करने योग्य टर्बोजेट इंजन का निर्माण और असेंबली।
- डीआरडीओ के प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम के तहत उद्योग भागीदार हैं।

परीक्षा फोकस बिंदु:

• इंजन: स्वदेशी एक्सपेंडेबल टर्बोजेट इंजन (ETJE)।
• थ्रस्ट क्लास: 350 किग्रा।
• डेवलपर: जीटीआरई, डीआरडीओ।
• मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर: आजाद इंजीनियरिंग, हैदराबाद।
• प्रशासनिक मंत्रालय: रक्षा मंत्रालय।
• संभावित अनुप्रयोग: क्रूज मिसाइलें, यूएवी, घूमने वाले युद्ध सामग्री।
• जीटीआरई स्थान: बेंगलुरु।
• डीआरडीओ की स्थापना: 1958।
• संबंधित कार्यक्रम: कावेरी इंजन कार्यक्रम।
• पहल: रक्षा में आत्मनिर्भर भारत।

DRDO ने लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल (LRSAM) 'कुश' का पहला उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक किया

- रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) ने ओडिशा के तट पर डॉ APJ अब्दुल कलाम द्वीप से स्वदेशी लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल (LRSAM) 'कुश' का पहला उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक किया।
- मिसाइल ने एक उच्च गति, उच्च ऊंचाई वाले इलेक्ट्रॉनिक हवाई लक्ष्य को सफलतापूर्वक भेद दिया, जो एक स्वदेशी लंबी दूरी की वायु रक्षा प्रणाली विकसित करने के भारत के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।

प्रोजेक्ट कुश के बारे में:

- प्रोजेक्ट कुश एक स्वदेशी लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल (एलआरएसएएम) कार्यक्रम है जिसे डीआरडीओ द्वारा विकसित किया जा रहा है ताकि हवाई खतरों के व्यापक स्पेक्ट्रम के खिलाफ क्षेत्र की वायु रक्षा प्रदान की जा सके।

प्रमुख विशेषताएं:

• लंबी दूरी की अवरोधन क्षमता।
• बहु-लक्ष्य जुड़ाव।
• नेटवर्क-केंद्रित संचालन।
• सभी मौसम क्षमता।
• उच्च गतिशीलता।
• एकीकृत आदेश और नियंत्रण।
• स्वदेशी रडार और अग्नि-नियंत्रण प्रणाली।

सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल (एसएएम) क्या है?

- सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल (एसएएम) दुश्मन के हवाई लक्ष्यों को रोकने और नष्ट करने के लिए जमीन से लॉन्च की जाने वाली मिसाइल है।

लक्ष्य:

• जैसे विमान।
• हेलीकॉप्टर।
• क्रूज मिसाइलें।
• ड्रोन।
• हवाई चेतावनी और निगरानी विमान।

वायु रक्षा मिसाइलों के प्रकार

प्रकार	विशिष्ट रेंज	उदाहरण
बहुत कम दूरी (वीएसएचओआरएडी)	10 किमी तक	वीएसएचओआरएडीएस
शॉर्ट रेंज (SRSAM)	10-40 किमी	वीएल-एसआरएसएएम
मध्यम श्रेणी (एमआरएसएएम)	40-100 किमी	एमआरएसएएम (बराक-8)
लंबी दूरी (LRSAM)	100 किमी से ऊपर	कुश

तुलना: Kusha vs S-400

विशेषता	कुश	एस-400 ट्रायम्फ
मूल	भारत	रूस
डेवलपर	डीआरडीओ	अल्माज़-एंटे
प्रकार	लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल	लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल
उद्देश्य	विमान, क्रूज मिसाइलों और ड्रोन के खिलाफ वायु रक्षा	विमान, क्रूज मिसाइलों और कुछ बैलिस्टिक मिसाइल खतरों सहित बहुस्तरीय वायु रक्षा
स्थिति	विकास और परीक्षण के तहत	भारतीय वायु सेना के साथ परिचालन

- नोट: कुश को अक्सर लंबी दूरी की वायु रक्षा के मामले में एस -400 के लिए भारत के स्वदेशी समकक्ष के रूप में वर्णित किया जाता है, लेकिन इसे एक समर्पित बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर के रूप में डिजाइन नहीं किया गया है।

भारत की वायु रक्षा प्रणाली:

प्रणाली	मूल	रेंज श्रेणी
आकाश	भारत	मध्यम श्रेणी
आकाश-एनजी	भारत	मध्यम श्रेणी (अगली पीढ़ी)
एमआरएसएएम (बराक-8)	भारत-इज़राइल	मध्यम श्रेणी
वीएल-एसआरएसएएम	भारत	लघु सीमा
क्यूआरएसएएम	भारत	त्वरित प्रतिक्रिया
कुश	भारत	लंबी दूरी की
एस-400 ट्रायम्फ	रूस	लंबी दूरी की

संबंधित डीआरडीओ मिसाइल कार्यक्रम:

- आकाश मिसाइल प्रणाली।
- आकाश-एनजी।
- QRSAM (क्विक रिएक्शन सरफेस-टू-एयर मिसाइल)।
- वीएल-एसआरएसएएम।
- एस्ट्रा हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल।
- ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल।
- प्रलय अर्ध-बैलिस्टिक मिसाइल।
- अग्नि बैलिस्टिक मिसाइल श्रृंखला।
- पिनाका मल्टी-बैरल रॉकेट लॉन्चर।

डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप के बारे में:

स्थान	ओडिशा के तट से दूर
पूर्व नाम	व्हीलर द्वीप
नाम बदला गया	2015
द्वारा प्रबंधित	इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज (आईटीआर), डीआरडीओ

महत्व

- भारत की प्रमुख मिसाइल परीक्षण सुविधा।

परीक्षण के लिए उपयोग किया जाता है:

- अग्नि मिसाइलें।
- पृथ्वी मिसाइलें।
- ब्रह्मोस।
- आकाश।
- कुश।
- बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा इंटरसेप्टर।

महत्वपूर्ण रक्षा संगठन

संगठन	हेडक्वार्टर्स
डीआरडीओ	नई दिल्ली
इसरो	बेंगलुरु
एचएएल	बेंगलुरु
बीईएल	बेंगलुरु
बीडीएल	हैदराबाद

- एडीए बेंगलुरु

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल):

- स्थापित: 1954।
- मुख्यालय: बेंगलुरु।
- अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक: मनोज जैन
- नवरत्न रक्षा पीएसयू।

विशेषज्ञता:

- रडार।
- इलेक्ट्रॉनिक युद्ध।
- कमांड और कंट्रोल सिस्टम।
- रक्षा संचार प्रणाली।
- स्तरित वायु रक्षा

परीक्षा फोकस बिंदु:

- मिसाइल: कुश लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल (LRSAM)।
- डेवलपर: DRDO।
- पहली उड़ान परीक्षण: 23 जुलाई 2026।
- परीक्षण स्थल: डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, ओडिशा।
- प्रकार: लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल।
- लक्ष्य: विमान, क्रूज मिसाइल, यूएवी और एईडब्ल्यू एंड सी विमान।
- प्रशासनिक मंत्रालय: रक्षा मंत्रालय।
- संबंधित पहल: आत्मनिर्भर भारत।
- मिसाइल परीक्षण सुविधा: एकीकृत परीक्षण रेंज (आईटीआर), ओडिशा।
- तुलना: स्वदेशी लंबी दूरी की वायु रक्षा प्रणाली भारत की स्तरित वायु रक्षा का पूरक है।

भारत और रोमानिया ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, शिक्षा और खेल के क्षेत्र में तीन समझौतों पर हस्ताक्षर किए

- भारत और रोमानिया ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी, शिक्षा और खेल के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए तीन समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। इन समझौतों का उद्देश्य वैज्ञानिक अनुसंधान, नवाचार, शैक्षणिक सहयोग, खेल विकास और लोगों से लोगों के आदान-प्रदान को बढ़ावा देना है, जिससे मध्य और पूर्वी यूरोप के साथ भारत का जुड़ाव गहरा हो सके।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी समझौता:

- विज्ञान और प्रौद्योगिकी (S&T) समझौता ज्ञापन का उद्देश्य वैज्ञानिक अनुसंधान, नवाचार और उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग को बढ़ावा देना है। इसमें संयुक्त अनुसंधान परियोजनाएं, वैज्ञानिकों का आदान-प्रदान, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, स्टार्टअप सहयोग, क्षमता निर्माण और एआई, जैव प्रौद्योगिकी और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग शामिल है।

शिक्षा समझौता:

- शिक्षा समझौता ज्ञापन का उद्देश्य छात्र और संकाय आदान-प्रदान, संयुक्त अनुसंधान, विश्वविद्यालय साझेदारी, छात्रवृत्ति और कौशल विकास के माध्यम से अकादमिक सहयोग को मजबूत करना है। यह उच्च शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण को बढ़ावा देकर राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020 के उद्देश्यों का भी समर्थन करता है।

खेल समझौता:

- खेल समझौता ज्ञापन एथलीटों, कोचों और खेल विशेषज्ञों के आदान-प्रदान के माध्यम से खेल और शारीरिक शिक्षा में सहयोग को बढ़ावा देता है। इसमें खेल प्रशिक्षण, खेल विज्ञान, खेल चिकित्सा, युवा विकास, बुनियादी ढांचा और खेल उत्कृष्टता बढ़ाने के लिए क्षमता निर्माण शामिल है।

भारत-रोमानिया द्विपक्षीय संबंध:

- भारत और रोमानिया ने 1948 में राजनयिक संबंध स्थापित किए और सात दशकों से अधिक समय तक मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखे हैं। व्यापार और निवेश, सूचना प्रौद्योगिकी, फार्मास्यूटिकल्स, रक्षा, कृषि, नवीकरणीय ऊर्जा, संस्कृति, शिक्षा और वैज्ञानिक अनुसंधान को शामिल करने के लिए संबंध का धीरे-धीरे विस्तार हुआ है। भारतीय दूतावास बुखारेस्ट में स्थित है, जबकि रोमानिया नई दिल्ली में अपना दूतावास रखता है।

व्यापार और आर्थिक संबंध:

- दोनों देशों के बीच व्यापार लगातार बढ़ रहा है। रोमानिया को भारत के प्रमुख निर्यात में फार्मास्यूटिकल्स, इंजीनियरिंग सामान, कपड़ा, रसायन, ऑटोमोबाइल और आईटी सेवाएं शामिल हैं, जबकि रोमानिया भारत को मशीनरी, विद्युत उपकरण, औद्योगिक उत्पाद, धातुकर्म उत्पाद और रसायन निर्यात करता है।

रोमानिया के बारे में:

- रोमानिया दक्षिण-पूर्वी यूरोप में स्थित एक देश है जिसकी राजधानी बुखारेस्ट में है। आधिकारिक भाषा रोमानियाई है, और राष्ट्रीय मुद्रा रोमानियाई ल्यू (आरओएन) है। रोमानिया 2004 में नाटो का सदस्य बना और 2007 में यूरोपीय संघ में शामिल हो गया, जिससे यह यूरोपीय क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण रणनीतिक भागीदार बन गया।
- राष्ट्रपति: निकुसोर डैन
- प्रधान मंत्री: इली बोलोजन

रोमानिया की भौगोलिक विशेषताएं:

- रोमानिया की सीमा यूक्रेन, मोल्दोवा, हंगरी, सर्बिया और बुल्गारिया से लगती है और काला सागर के साथ एक समुद्र तट है। डेन्यूब नदी, यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी, काला सागर में खाली होने से पहले रोमानिया से होकर बहती है, जो पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण डेन्यूब डेल्टा, यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल और यूरोप के सबसे बड़े आर्द्रभूमि पारिस्थितिक तंत्र में से एक है। यह देश कार्पेथियन पर्वत का भी घर है, जो यूरोप की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है।

काला सागर:

- काला सागर की सीमा रोमानिया, बुल्गारिया, तुर्की, जॉर्जिया, रूस और यूक्रेन से लगती है। यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ऊर्जा परिवहन, समुद्री सुरक्षा और क्षेत्रीय भू-राजनीति के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, जो यूरोप और एशिया के बीच एक प्रमुख कड़ी के रूप में कार्य करता है।

डेन्यूब नदी:

- डेन्यूब नदी, लगभग 2,850 किमी लंबी, वोल्गा के बाद यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। यह जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट में निकलती है और डेन्यूब डेल्टा के माध्यम से काला सागर में बहने से पहले जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, हंगरी, क्रोएशिया, सर्बिया, बुल्गारिया, रोमानिया, मोल्दोवा और यूक्रेन से होकर बहती है।

भारत का वैज्ञानिक सहयोग ढांचा:

- भारत में अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक सहयोग विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) द्वारा समन्वित किया जाता है। विभाग दुनिया भर के भागीदार देशों के साथ संयुक्त अनुसंधान कार्यक्रमों, नवाचार, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, क्षमता निर्माण और वैज्ञानिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देता है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP), 2020:

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020 छात्र और संकाय गतिशीलता, वैश्विक शैक्षणिक सहयोग, संयुक्त अनुसंधान कार्यक्रम, बहु-विषयक शिक्षा और विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ साझेदारी को बढ़ावा देकर उच्च शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण को प्रोत्साहित करती है।

खेलो इंडिया कार्यक्रम:

- युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा 2018 में शुरू किए गए खेलो इंडिया कार्यक्रम का उद्देश्य जमीनी स्तर पर खेल प्रतिभाओं की पहचान करना, खेल के बुनियादी ढांचे में सुधार करना, कोचिंग मानकों को बढ़ाना और देश में एक मजबूत खेल संस्कृति को बढ़ावा देना है। भारत-रोमानिया खेल समझौता ज्ञापन जैसे अंतर्राष्ट्रीय खेल सहयोग समझौते, इन राष्ट्रीय उद्देश्यों के पूरक हैं।

यूरोपीय संघ (EU):

- यूरोपीय संघ (ईयू) की स्थापना 1993 में मास्ट्रिच संधि के माध्यम से की गई थी और इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। इसमें 27 सदस्य देश शामिल हैं और यह दुनिया के सबसे बड़े आर्थिक और राजनीतिक संघों में से एक का प्रतिनिधित्व करता है। रोमानिया 2007 से यूरोपीय संघ का सदस्य है।

अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में रोमानिया:

- रोमानिया संयुक्त राष्ट्र (यूएन), यूरोपीय संघ (ईयू), उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (नाटो), विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ), अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) और विश्व बैंक सहित कई प्रमुख अंतरराष्ट्रीय संगठनों का सदस्य है, जो वैश्विक शासन और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में इसकी सक्रिय भूमिका को दर्शाता है।

परीक्षा फोकस

• देश: रोमानिया
• राजधानी: बुखारेस्ट
• मुद्रा: रोमानियाई ल्यू (आरओएन)
• हस्ताक्षरित: विज्ञान और प्रौद्योगिकी, शिक्षा और खेल
• राजनयिक संबंधों की स्थापना: 1948
• रोमानिया नाटो में शामिल हुआ: 2004
• रोमानिया यूरोपीय संघ में शामिल हुआ: 2007
• प्रमुख नदी: डेन्यूब
• प्रमुख सागर: काला सागर

• भारतीय नोडल विभाग (एस एंड टी): विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी)
• संबंधित भारतीय नीति: राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020

केंद्र ने विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में सचिवों की नियुक्ति की

- कैबिनेट की नियुक्ति समिति (एसीसी) ने एक बड़े नौकरशाही फेरबदल को मंजूरी दी, जिसमें 13 वरिष्ठ अधिकारियों को भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में सचिव के रूप में नियुक्त किया गया।

प्रमुख नियुक्तियां:

शिक्षा मंत्रालय:

• नरेश पाल गंगवार को उच्च शिक्षा विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है।
• टी. के. अनिल कुमार को स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग का सचिव नियुक्त किया गया
• विनीत जोशी को पंचायती राज मंत्रालय के सचिव के रूप में स्थानांतरित किया गया है।

नौकरशाही फेरबदल क्यों महत्वपूर्ण हैं?

समय-समय पर होने वाले फेरबदल से सरकार को निम्नलिखित में मदद मिलती है:

• प्रशासनिक दक्षता में सुधार करें।
• प्रभावी नीति कार्यान्वयन सुनिश्चित करें।
• विभिन्न क्षेत्रों में अधिकारियों की विशेषज्ञता का उपयोग करें।
• अंतर-मंत्रालयी समन्वय बढ़ाना।
• शासन और सार्वजनिक सेवा वितरण को मजबूत करना।

मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (ACC):

- कैबिनेट की नियुक्ति समिति (एसीसी) भारत सरकार में शीर्ष पदों पर वरिष्ठ सिविल सेवकों की नियुक्ति के लिए जिम्मेदार सर्वोच्च प्राधिकरण है।

मिश्रण

- अध्यक्ष: भारत के प्रधान मंत्री।
- सदस्य: केंद्रीय गृह मंत्री।
- कार्य
- भारत सरकार में सचिवों की नियुक्ति करता है।
- अतिरिक्त सचिवों और वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति करता है।
- महत् वपूर्ण सरकारी संगठनों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रमुखों की नियुक्तियों को मंजूरी दी।
- एसीसी अनुमोदन की आवश्यकता वाले प्रमुख संवैधानिक और वैधानिक पदों पर नियुक्तियों की देखरेख करता है।

भारत सरकार के सचिव:

- भारत सरकार का एक सचिव किसी मंत्रालय या विभाग का प्रशासनिक प्रमुख होता है और कैबिनेट सचिव के बाद उस मंत्रालय में वरिष्ठतम सिविल सेवक होता है।

कार्य:

- नीतिगत मामलों पर मंत्री को सलाह देता है।
- नीति कार्यान्वयन की निगरानी करता है।
- अन्य मंत्रालयों के साथ समन्वय करता है।
- प्रशासन और वित्त का प्रबंधन करता है।
- मंत्रालय के प्रधान लेखा अधिकारी के रूप में कार्य करता है।

कैबिनेट सचिवालय:

- मुख्यालय: नई दिल्ली
- प्रमुख: कैबिनेट सचिव (डॉ. टी. वी. सोमनाथन)

कार्य:

- प्रधान मंत्री और कैबिनेट की सहायता करता है।
- मंत्रालयों के बीच समन्वय।
- कैबिनेट के फैसलों को लागू करता है।
- अंतर-मंत्रालयी समन्वय की सुविधा प्रदान करता है।

कैबिनेट सचिव:

- कैबिनेट सचिव भारत में सबसे वरिष्ठ सिविल सेवक होता है और कैबिनेट सचिवालय का प्रमुख होता है।

कार्य:

- केंद्र सरकार के मुख्य समन्वयक।
- सिविल सेवा बोर्ड के प्रमुख।
- प्रशासनिक मामलों पर प्रधान मंत्री और कैबिनेट के प्रधान सलाहकार।
- मंत्रालयों के बीच समन्वय सुनिश्चित करता है।

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी)

- मंत्रालय: कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

कार्य

- कार्मिक प्रशासन।
- सिविल सेवा सुधार।
- आईएएस अधिकारियों का कैडर प्रबंधन।
- केंद्रीय स्टाफिंग।
- सिविल सेवकों का प्रशिक्षण।
- सतर्कता और सेवा मायने रखती है।

वरिष्ठ सिविल सेवा पदों का पदानुक्रम:

श्रेणी	पद
	• कैबिनेट सचिव
सेक्रेटरी	
	• विशेष सचिव
	• अपर सचिव
	• संयुक्त सचिव
निदेशक	
	• उप सचिव
	• अवर सचिव

महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रावधान

- अनुच्छेद 53: संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित है।
- अनुच्छेद 74: मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देती है।
- अनुच्छेद 77: भारत सरकार के कार्य का संचालन।
- अनुच्छेद 309: संघ या राज्यों में सेवारत व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तें।

पंचायती राज मंत्रालय

- स्थापित: 2004।
- 73वें संविधान संशोधन और ग्रामीण स्थानीय स्वशासन को मजबूत करने के लिए जिम्मेदार।

परीक्षा फोकस बिंदु:

- द्वारा अनुमोदित नियुक्तियाँ: कैबिनेट की नियुक्ति समिति (एसीसी)।
- एसीसी अध्यक्ष: प्रधान मंत्री।
- एसीसी सदस्य: केंद्रीय गृह मंत्री।
- सचिव: किसी मंत्रालय/विभाग का प्रशासनिक प्रमुख।
- सर्वोच्च सिविल सेवक: कैबिनेट सचिव।
- आईएएस का कैडर प्रबंधन: डीओपीटी।
- प्रासंगिक संवैधानिक अनुच्छेद: 53, 74, 77, 309।
- पंचायती राज मंत्रालय की स्थापना: 2004।
- नए उच्च शिक्षा सचिव: नरेश पाल गंगवार।
- नए स्कूल शिक्षा और साक्षरता सचिव: टी. के. अनिल कुमार

इंफोसिस ने आशीष कुमार दास को सीईओ और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया

- इंफोसिस लिमिटेड ने आशीष कुमार दास को अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) और प्रबंध निदेशक (एमडी) नामित नियुक्त किया है। वह 1 अप्रैल 2027 से सीईओ और एमडी की भूमिका ग्रहण करेंगे, जो सलिल पारेख का स्थान लेंगे, जिनका दूसरा कार्यकाल 31 मार्च 2027 को समाप्त होगा। परिवर्तन प्रक्रिया अक्टूबर 2026 में शुरू होगी, जिससे नेतृत्व की निरंतरता और सुचारू उत्तराधिकार सुनिश्चित होगा।

इंफोसिस लिमिटेड के बारे में:

- इंफोसिस लिमिटेड भारत की अग्रणी बहुराष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) सेवाओं और परामर्श कंपनियों में से एक है।
- स्थापित: 2 जुलाई 1981

- मुख्यालय: बेंगलुरु, कर्नाटक
- संस्थापक: एनआर नारायण मूर्ति और छह अन्य सह-संस्थापक
- अध्यक्ष: नंदन नीलेकणि

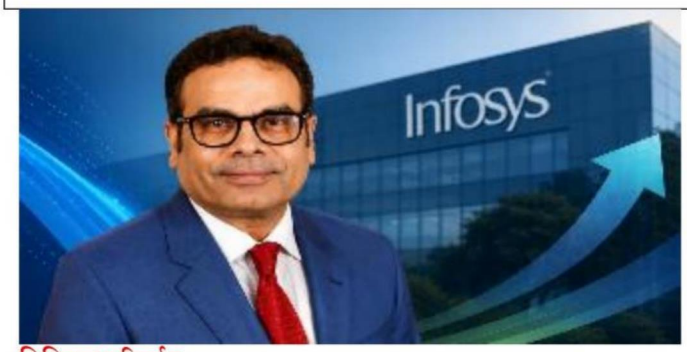

डिजिटल परिवर्तन:

- डिजिटल परिवर्तन दक्षता, ग्राहक अनुभव और नवाचार में सुधार के लिए व्यावसायिक प्रक्रियाओं में डिजिटल प्रौद्योगिकियों के एकीकरण को संदर्भित करता है।

प्रमुख प्रौद्योगिकियां:

- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई)।
- क्लाउड कंप्यूटिंग।
- इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT)।
- बिग डेटा एनालिटिक्स।
- ब्लॉकचेन।
- मशीनी परिचालन।
- साइबर सुरक्षा।

प्रमुख भारतीय आईटी कंपनियां:

- अतिथि हेडक्वार्टर्स
- इंफोसिस बेंगलुरु
- टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) मुंबई
- विप्रो बेंगलुरु
- एचसीएलटेक नोएडा
- टेक महिंद्रा पुणे

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी)

- स्थापित: 1988 (वैधानिक स्थिति: 1992)
- अध्यक्ष: तुहिन कांता पांडे
- मुख्यालय: मुंबई

कार्य:

- निवेशकों की रक्षा करें।
- प्रतिभूति बाजारों को विनियमित करना।
- निष्पक्ष व्यापार को बढ़ावा देना।
- इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकें।
- सूचीबद्ध कंपनियों को विनियमित करें।

प्रमुख इंफोसिस उत्पाद:

- फिनैकल (कोर बैंकिंग समाधान)।
- इंफोसिस पुखराज (एआई प्लेटफॉर्म)।
- इंफोसिस कोबाल्ट (क्लाउड प्लेटफॉर्म)।
- इंफोसिस बीपीएम।

परीक्षा फोकस बिंदु:

- कंपनी: इंफोसिस लिमिटेड।
- नए सीईओ और एमडी पदनामित : आशीष कुमार दास
- प्रभावी तिथि: 1 अप्रैल 2027।
- निवर्तमान सीईओ और एमडी: सलिल पारेख।
- मुख्यालय: बेंगलुरु, कर्नाटक।
- स्थापित: 1981।
- अध्यक्ष: नंदन नीलेकणि।
- उद्योग: सूचना प्रौद्योगिकी और परामर्श।
- प्रमुख उत्पाद: फिनेकल।
- उद्योग संघ: नैसकॉम।
- सूचीबद्ध कंपनियों का नियामक: सेबी।

राजनाथ सिंह ने तीनों सेनाओं के पहले सर्व-महिला नौकायन अभियान 'समुद्र प्रदक्षिणा' को झंडी दिखाकर रवाना किया

- रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 314 दिनों की वैश्विक यात्रा के सफल समापन को चिह्नित करते हुए भारत के पहले त्रि-सेवा सर्व-महिला परिभ्रमण नौकायन अभियान 'समुद्र प्रदक्षिणा' को हरी झंडी दिखाई।
- भारतीय सेना के नौकायन पोत (आईएएसवी) त्रिवेणी पर सवार होकर, भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायु सेना की नौ महिला अधिकारी चार महासागरों में लगभग 25,500 समुद्री मील की दूरी तय करने के बाद मुंबई लौट आईं, जो नारी शक्ति, त्रि-सेवा संयुक्तता और आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक है।

परिभ्रमण क्या है?

- परिभ्रमण एक ऐसी यात्रा को संदर्भित करता है जो सभी प्रमुख मेरिडियन को पार करके और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त नौकायन मानदंडों को पूरा करते हुए शुरुआती बिंदु पर लौटकर पूरी तरह से पृथ्वी का चक्कर लगाती है।

वैश्विक परिभ्रमण के लिए आवश्यकताएँ

• सभी देशांतरों को पार करें।
• भूमध्य रेखा को पार करें।
• अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करें।
• दुनिया भर में लगातार यात्रा करें।
• जहां लागू हो प्रमुख केप को गोल करें।

आईएएसवी त्रिवेणी:

- IASV त्रिवेणी (भारतीय सेना नौकायन पोत त्रिवेणी) एक स्वदेशी रूप से निर्मित 50 फुट का नौकायन पोत है जिसका उपयोग लंबी दूरी के समुद्री अभियानों और साहसिक नौकायन के लिए किया जाता है।

सुविधाऐं

- स्वदेशी डिजाइन और निर्माण।
- लंबी दूरी की समुद्री नौकायन क्षमता।

उच्च धीरज।

- चरम मौसम के माध्यम से नेविगेशन।
- साहसिक और सैन्य नौकायन मिशनों का समर्थन करता है।

त्रि-सेवा संयुक्तता क्या है?

- तीनों सेनाओं की संयुक्तता से तात्पर्य युद्ध प्रभावशीलता और संसाधन उपयोग में सुधार के लिए योजना, प्रशिक्षण, रसद और संचालन के लिए भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायु सेना के एकीकृत कामकाज से है।

सैन्य कूटनीति:

- सैन्य कूटनीति से तात्पर्य अंतरराष्ट्रीय संबंधों को मजबूत करने के लिए रक्षा सहयोग, सैन्य आदान-प्रदान, संयुक्त अभ्यास, बंदरगाह यात्राओं और मानवीय मिशनों के उपयोग से है।

महत्व:

- रणनीतिक साझेदारी बनाता है।
- रक्षा सहयोग बढ़ाता है।
- सद्भावना को बढ़ावा देता है।
- भारत की समुद्री पहुंच को मजबूत करता है।
- भारत की विदेश नीति के उद्देश्यों का समर्थन करता है।

तीन महान केप:

• अंतरीप	स्थान
• केप ऑफ गुड होप	दक्षिण अफ्रीका
• केप लीउविन	ऑस्ट्रेलिया
• केप हॉर्न	चिली

- ये केप दुनिया के सबसे चुनौतीपूर्ण समुद्री मार्गों में से हैं और वैश्विक परिभ्रमण में महत्वपूर्ण मील के पत्थर हैं।

ड्रेक मार्ग:

- ड्रेक पैसेज केप हॉर्न (दक्षिण अमेरिका) और अंटार्कटिका के बीच समुद्र का एक संकीर्ण खंड है, जो अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है।

महत्व

- दुनिया के सबसे उबड़-खाबड़ समुद्री मार्गों में से एक।
- तेज हवाओं और भारी लहरों के लिए जाना जाता है।
- वैश्विक परिभ्रमण के लिए महत्वपूर्ण मार्ग।

अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा (IDL):

- अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा एक काल्पनिक रेखा है जो प्रशांत महासागर में लगभग 180° देशांतर के साथ स्थित है।

महत्व

- इसे पार करने से कैलेंडर की तारीख एक दिन बदल जाती है।
- अंतरराष्ट्रीय टाइमकीपिंग के लिए उपयोग किया जाता है।

भारत के महत्वपूर्ण समुद्री अभियान:

• नाविका सागर परिक्रमा-I (2017-18) - भारतीय नौसेना की पहली महिला परिक्रमा।
• नाविका सागर परिक्रमा-II (2024-25) - INSV तारिणी पर दो महिलाओं की वैश्विक परिक्रमा।
• समुद्र प्रदक्षिणा (2025-26) - IASV त्रिवेणी पर पहली बार त्रि-सेवा सभी महिला परिक्रमा।

केप हॉर्नर्स

- केप हॉर्नर्स बिरादरी में नाविक शामिल हैं जिन्होंने दुनिया के सबसे चुनौतीपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक, केप हॉर्न को सफलतापूर्वक गोल किया है।

परीक्षा फोकस बिंदु:

• एक्सपीडिशन: समुद्र प्रदक्षिणा
• प्रकार: पहली बार त्रि-सेवा सभी महिला परिभ्रमण नौकायन अभियान।
• ध्वजांकित किया गया: राजनाथ सिंह।
• पोत: IASV त्रिवेणी।
• चालक दल: सेना, नौसेना और वायु सेना की नौ महिला अधिकारी।
• अवधि: 314 दिन।
• तय की गई दूरी: लगभग 25,500 समुद्री मील।
• प्रमुख उपलब्धियां: भूमध्य रेखा को दो बार पार किया, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पार किया, तीन महान केप को गोल किया, ड्रेक मार्ग को नेविगेट किया।
• थीम : नारी शक्ति, ट्राई-सर्विस जॉइंटनेस, आत्मनिर्भर भारत।
• संबंधित अवधारणा: सैन्य कूटनीति।

अमेरिका ने जबरन श्रम चिंताओं पर भारतीय वस्तुओं पर 10% शुल्क लगाया

- राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के तहत संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1974 के अमेरिकी व्यापार अधिनियम की धारा 301 के तहत भारत और कई अन्य देशों से आयात पर 10% अतिरिक्त टैरिफ लगाया है, जिसमें जबरन श्रम के माध्यम से उत्पादित वस्तुओं के खिलाफ अपर्याप्त प्रवर्तन पर चिंताओं का हवाला दिया गया है।
- भारत को 10% टैरिफ श्रेणी में रखा गया था, जबकि कई अन्य अर्थव्यवस्थाओं को 12.5% टैरिफ का सामना करना पड़ता है।
- यह उपाय अस्थायी वैश्विक टैरिफ की जगह लेता है जो समाप्त हो गया है और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में जबरन श्रम को लक्षित करने वाली एक व्यापक अमेरिकी व्यापार नीति का हिस्सा है।

टैरिफ क्या है?

- टैरिफ एक सरकार द्वारा आयातित वस्तुओं पर लगाया गया कर है। टैरिफ का उपयोग घरेलू उद्योगों की रक्षा करने, राजस्व उत्पन्न करने, व्यापार घाटे को कम करने या अन्य देशों की व्यापार नीतियों को प्रभावित करने के लिए किया जाता है।
- टैरिफ के प्रकार:
- यथामूल्य टैरिफ - आयातित माल के मूल्य के प्रतिशत के रूप में लगाया जाता है।
- विशिष्ट टैरिफ - प्रति यूनिट एक निश्चित राशि के रूप में प्रभारित किया जाता है।
- सुरक्षात्मक टैरिफ - घरेलू उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाता है।
- राजस्व टैरिफ - मुख्य रूप से सरकारी राजस्व उत्पन्न करने के लिए लगाया जाता है।

जबरन श्रम क्या है?

- अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) के अनुसार, जबरन श्रम किसी व्यक्ति से सजा की धमकी के तहत और स्वैच्छिक सहमति के बिना निकाले गए काम या सेवा को संदर्भित करता है।

सामान्य प्रपत्र

• ऋण बंधन।
• मानव तस्करी।
• जबरन बाल श्रम किया जाता है।
• जबरन जेल श्रम।
• शोषक प्रवासी मजदूर।

301 के अमेरिकी व्यापार अधिनियम की धारा 1974:

- धारा 301 संयुक्त राज्य अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि (यूएसटीआर) को अनुचित विदेशी व्यापार प्रथाओं की जांच करने और उनका जवाब देने का अधिकार देती है जो अमेरिकी वाणिज्य पर बोझ डालती हैं या प्रतिबंधित करती हैं।

प्रमुख विशेषताऐं:

- अनुचित व्यापार प्रथाओं की जांच करता है।
- अमेरिका को टैरिफ या अन्य व्यापार प्रतिबंध लगाने के लिए अधिकृत करता है।
- व्यापार प्रवर्तन तंत्र के रूप में उपयोग किया जाता है।
- अक्सर बौद्धिक संपदा, बाजार पहुंच, सब्सिडी और श्रम मानकों से संबंधित प्रथाओं के खिलाफ लागू किया जाता है।

संयुक्त राज्य अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि (यूएसटीआर):

- यूएसटीआर अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नीति के विकास और समन्वय के लिए जिम्मेदार प्रमुख एजेंसी है।

विशेष विवरण

स्थापित	1962
हेडक्वार्टर्स	वाशिंगटन, डी.सी.
को रिपोर्ट करता है	संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति

कार्य

- व्यापार समझौतों पर बातचीत करता है।
- धारा 301 की जांच करता है।
- विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) में अमेरिका का प्रतिनिधित्व करता है।
- अमेरिकी व्यापार नीति विकसित करता है।

भारत-अमेरिका व्यापार संबंध:

- भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया के सबसे बड़े द्विपक्षीय व्यापार संबंधों में से एक साझा करते हैं, जिसमें वस्तुओं, सेवाओं, निवेश, प्रौद्योगिकी, रक्षा और डिजिटल व्यापार को शामिल किया गया है।

अमेरिका को प्रमुख भारतीय निर्यात:

- फार्मास्यूटिकल्स।
- इंजीनियरिंग सामान।
- रत्न और आभूषण।
- कपड़ा और परिधान।
- आईटी सेवाएं।
- कार्बनिक रसायन।
- अमेरिका से प्रमुख आयात
- कच्चा तेल और एलएनजी।
- विमान और रक्षा उपकरण।
- इलेक्ट्रॉनिक्स।
- यंत्र समूह।
- चिकित्सा उपकरण।

भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौता (BTA):

- भारत और अमेरिका बाजार पहुंच का विस्तार करने और व्यापार बाधाओं को कम करने के लिए एक द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहे हैं।

प्रस्तावित क्षेत्र:

- माल और सेवाएं।
- कृषि।
- डिजिटल व्यापार।
- ख़रीदी वस्तु।
- बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर)।
- आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन।

विश्व व्यापार संगठन (WTO):

- विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) राष्ट्रों के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करने वाला वैश्विक निकाय है।

स्थापित	1 जनवरी 1995
हेडक्वार्टर्स	जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड
महानिदेशक	ओकोन्जो-इवेला के खतरे
के उत्तराधिकारी	टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौता (GATT)

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ)

- आईएलओ एकमात्र त्रिपक्षीय संयुक्त राष्ट्र विशेष एजेंसी है, जो सरकारों, नियोक्ताओं और श्रमिकों को एक साथ लाती है।

विशेष	विवरण
स्थापित	1919
महानिदेशक	गिल्बर्ट हाउंगबो
हेडक्वार्टर्स	जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड

• संयुक्त राष्ट्र एजेंसी बन गई 1946

जबरन श्रम के खिलाफ भारत का कानूनी ढांचा:

- भारत में जबरन श्रम के खिलाफ संवैधानिक और वैधानिक सुरक्षा उपाय हैं।

संवैधानिक प्रावधान:

• अनुच्छेद 23 – मानव तस्करी और जबरन श्रम (बेगर) पर प्रतिबंध लगाता है।
• अनुच्छेद 24 – 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक व्यवसायों में नियोजित करने पर प्रतिबंध लगाता है।

प्रमुख कानून:

• बंधुआ श्रम प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम, 1976
• बाल और किशोर श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986
• न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (अब वेतन संहिता, 2019 के तहत समाविष्ट)।
• व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता, 2020

व्यापार उपाय:

- देश घरेलू उद्योगों को अनुचित व्यापार प्रथाओं से बचाने के लिए व्यापार उपायों का उपयोग करते हैं।
- प्रमुख व्यापार उपाय:
- एंटी-डंपिंग ड्यूटी - उचित मूल्य से कम बेचे जाने वाले सामान के खिलाफ।
- काउंटरवेलिंग ड्यूटी (सीवीडी) - निर्यातक देशों द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी को ऑफसेट करता है।
- सेफगार्ड ड्यूटी - आयात में अचानक वृद्धि के खिलाफ अस्थायी सुरक्षा।
- टैरिफ – आयातित वस्तुओं पर कर।

अतिरिक्त तथ्य:

- टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौता (GATT)
- 1947 में स्थापित।
- 1995 में विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।
- इसका उद्देश्य टैरिफ को कम करना और वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देना है।

परीक्षा फोकस बिंदु:

• टैरिफ लगाने वाला देश: संयुक्त राज्य अमेरिका।
• भारत पर टैरिफ: 10%।
• कानूनी आधार: अमेरिकी व्यापार अधिनियम, 1974 की धारा 301।
• कारण: आपूर्ति श्रृंखलाओं में जबरन श्रम के खिलाफ कथित अपर्याप्त प्रवर्तन।
• जांच प्राधिकरण: संयुक्त राज्य अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि (यूएसटीआर)।
• प्रभावित देश: लगभग 60.
• वैश्विक व्यापार निकाय: विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ)।
• श्रम पर संयुक्त राष्ट्र एजेंसी: अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ)।
• जबरन श्रम के खिलाफ भारतीय संवैधानिक प्रावधान: अनुच्छेद 23।
• GATT का उत्तराधिकारी: विश्व व्यापार संगठन (1995)।

NPCI का प्रस्तावित 'UPI मेटा' फ्रेमवर्क प्रतिस्पर्धा संबंधी चिंताओं को बढ़ाता है

- नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने UPI मेटा (जिसे UPI चेकआउट भी कहा जाता है) नामक एक नए भुगतान ढांचे का प्रस्ताव दिया है, जो उपयोगकर्ताओं को एक-क्लिक UPI भुगतान के लिए एक व्यापारी के ऐप या वेबसाइट पर पसंदीदा UPI ID सहेजने में सक्षम बनाकर ऑनलाइन भुगतान को सरल बनाता है। हालांकि, कई छोटी फिनटेक कंपनियों ने चिंता व्यक्त की है कि यह प्रस्ताव फोनपे और गूगल पे जैसे प्रमुख यूपीआई ऐप के बाजार प्रभुत्व को मजबूत कर सकता है, जिससे भारत के डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र में प्रतिस्पर्धा कम हो सकती है।

UPI मेटा (UPI चेकआउट) क्या है?

- यूपीआई मेटा एक प्रस्तावित भुगतान ढांचा है जो ग्राहकों को ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म या मर्चेंट वेबसाइट पर अपनी पसंदीदा यूपीआई आईडी या भुगतान एप्लिकेशन को सहेजने में सक्षम बनाता है। भविष्य की खरीदारी के दौरान, उपयोगकर्ता बार-बार यूपीआई एप्लिकेशन का चयन किए बिना, एक क्लिक से भुगतान कर सकते हैं।

छोटे UPI ऐप्स क्यों चिंतित हैं?

- छोटे भुगतान सेवा प्रदाताओं का मानना है कि यह प्रस्ताव अनजाने में पहले से ही प्रमुख यूपीआई अनुप्रयोगों का पक्ष ले सकता है।

प्रमुख चिंताएं

- उपयोगकर्ता स्थायी रूप से एक डिफ़ॉल्ट भुगतान ऐप से जुड़े रह सकते हैं।
- चेकआउट के दौरान छोटे UPI ऐप्स के लिए दृश्यता कम हो गई।
- बाजार की एकाग्रता में वृद्धि।
- नए प्रवेशकों के लिए उच्च बाधाएं।
- उपभोक्ता की पसंद और नवाचार में संभावित कमी।

भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई):

- नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) भारत के खुदरा भुगतान और निपटान प्रणालियों के संचालन के लिए जिम्मेदार एक छत्र संगठन है।

• स्थापित : 2008
• मुख्यालय: मुंबई
• गैर-पूर्व अध्यक्ष: अजय कुमार चौधरी
• एमडी और सीईओ: दिलीप आएंगे
• प्रकार: गैर-लाभकारी संगठन (धारा 8 कंपनी)
• द्वारा प्रचारित: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और भारतीय बैंक संघ (IBA)

कानूनी आधार **भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007**

NPCI के प्रमुख उत्पाद:

• यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई)।
• रुपे।
• तत्काल भुगतान सेवा (आईएमपीएस)।
• नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस (NACH)।
• भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस)।
• राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह (फास्टैग)।
• आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (एईपीएस)।

एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस (UPI):

- यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) एक तत्काल, इंटरऑपरेबल डिजिटल भुगतान प्रणाली है जो मोबाइल उपकरणों का उपयोग करके बैंक खातों के बीच धन के वास्तविक समय हस्तांतरण को सक्षम बनाती है।

सुविधाऐं

• 24×7 तत्काल भुगतान।
• बैंकों में इंटरऑपरेबल।
• व्यक्ति-से-व्यक्ति (P2P) और व्यक्ति-से-व्यापारी (P2M) लेनदेन का समर्थन करता है।
• क्यूआर कोड-आधारित भुगतान।
• अनुरोध और ऑटोपे सुविधाएं एकत्र करें।
• तत्काल भुगतान सेवा (आईएमपीएस) प्लेटफॉर्म पर निर्मित।

तत्काल भुगतान सेवा (आईएमपीएस):

- IMPS NPCI द्वारा संचालित एक वास्तविक समय इंटर-बैंक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम है।

सुविधाऐं

• पूरे वर्ष 24×7 उपलब्ध है।
• तत्काल निपटान।
• मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम और बैंक शाखाओं के माध्यम से पहुंच योग्य है।
• यूपीआई की तकनीकी रीढ़ बनाता है।

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और डिजिटल भुगतान:

- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के तहत भारत में भुगतान प्रणालियों को नियंत्रित करता है, जबकि NPCI देश के कई खुदरा भुगतान बुनियादी ढांचे प्लेटफार्मों का संचालन करता है।

आरबीआई की भूमिका

• भुगतान प्रणालियों को नियंत्रित करता है।
• भुगतान ऑपरेटरों को अधिकृत करता है।
• सुरक्षित और सुरक्षित डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देता है।
• वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करता है।

डिजिटल भुगतान में प्रतिस्पर्धा के मुद्दे:

- भारत के UPI इकोसिस्टम में तेजी से वृद्धि देखी गई है, जिसमें PhonePe और Google Pay मिलकर लगभग 80% UPI लेनदेन को संभालते हैं. एकाग्रता जोखिम को कम करने के लिए, NPCI ने पहले थर्ड-पार्टी UPI एप्लीकेशन के लिए 30% मार्केट शेयर कैप का प्रस्ताव दिया था, हालांकि इसका कार्यान्वयन दिसंबर 2026 तक स्थगित कर दिया गया है.

डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI):

- भारत का डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र इसके डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (DPI) का एक प्रमुख स्तंभ है।

प्रमुख घटक:

• आधार।
• यूपीआई।
• डिजिलॉकर।
• फास्टैग
• अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क।
• ओएनडीसी।

भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007:

- भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 भारत में भुगतान प्रणालियों को विनियमित करने के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है।

प्रमुख विशेषताऐं

- भारतीय रिज़र्व बैंक नामित नियामक प्राधिकरण है।
- भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों को अधिकृत करता है।
- भुगतान प्रणालियों की सुरक्षा और दक्षता सुनिश्चित करता है।
- उपभोक्ता हितों की रक्षा करता है।

परीक्षा फोकस बिंदु:

• प्रस्तावित ढांचा: UPI मेटा (UPI चेकआउट)।
• द्वारा प्रस्तावित: भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई)।
• उद्देश्य: पसंदीदा UPI ऐप/ID सेव करके एक-क्लिक UPI चेकआउट.
• चिंता: बाजार एकाग्रता में संभावित वृद्धि और प्रतिस्पर्धा में कमी।
• UPI नियामक: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI)।
• यूपीआई ऑपरेटर: एनपीसीआई।
• UPI लॉन्च: 2016।
• कानूनी ढांचा: भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007।
• यूपीआई की प्रौद्योगिकी रीढ़: तत्काल भुगतान सेवा (आईएमपीएस)।
• एनपीसीआई के प्रमोटर: आरबीआई और इंडियन बैंक्स एसोसिएशन (आईबीए)।

सेंट्रल केवाईसी (सीकेवाईसी): कई वित्तीय सेवाओं के लिए एक एकल केवाईसी

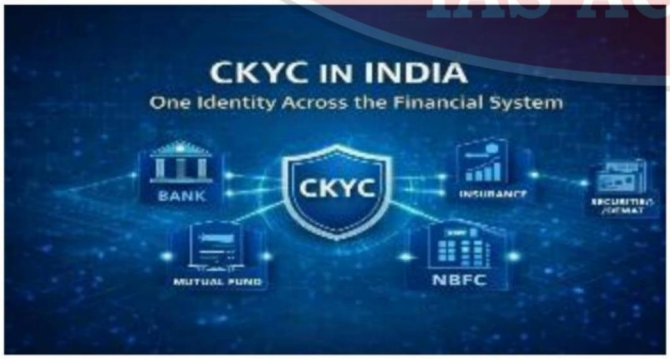

- सेंट्रल नो योर कस्टमर (सीकेवाईसी) सिस्टम ग्राहकों को केवल एक बार अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) प्रक्रिया को पूरा करने और बैंकों, म्यूचुअल फंड, बीमा कंपनियों, पेंशन फंड और एनबीएफसी जैसे कई विनियमित वित्तीय संस्थानों में इसका उपयोग करने में सक्षम बनाता है। प्रत्येक ग्राहक को एक अद्वितीय 14-अंकीय सीकेवाईसी पहचानकर्ता प्राप्त होता है, जो केवाईसी दस्तावेजों को बार-बार जमा करने को खत्म करने में मदद करता है और वित्तीय ऑनबोर्डिंग को सरल बनाता है। इस पहल ने नए सिरे से ध्यान आकर्षित किया है क्योंकि भारत वित्तीय क्षेत्र में निर्बाध ग्राहक पहचान के लिए सीकेवाईसी 2.0 ढांचे को मजबूत करने की तैयारी कर रहा है।

सीकेवाईसी क्या है?

- सेंट्रल नो योर कस्टमर (सीकेवाईसी) केवाईसी रिकॉर्ड का एक केंद्रीकृत भंडार है जो वित्तीय संस्थानों को बार-बार दस्तावेजों को एकत्र करने के बजाय एक अद्वितीय सीकेवाईसी पहचानकर्ता का उपयोग करके ग्राहक की सत्यापित केवाईसी जानकारी प्राप्त करने की अनुमति देता है।

सीकेवाईसी नंबर क्या है?

- सीकेवाईसी नंबर, जिसे केवाईसी आइडेंटिफायर (केआईएन) भी कहा जाता है, एक 14 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या है जो सीकेवाईसी प्रणाली में सफल पंजीकरण के बाद प्रत्येक ग्राहक को आवंटित की जाती है।

केंद्रीय केवाईसी रिकॉर्ड रजिस्ट्री (सीकेवाईसीआरआर):

- सेंट्रल केवाईसी रिकॉर्ड्स रजिस्ट्री (सीकेवाईसीआरआर) केवाईसी रिकॉर्ड को स्टोर करने और प्रबंधित करने के लिए जिम्मेदार केंद्रीय भंडार है।
- द्वारा संचालित भारत की प्रतिभूतिकरण परिसंपत्ति पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित की केंद्रीय रजिस्ट्री (CERSAI)
- उद्देश्यकेवाईसी रिकॉर्ड का केंद्रीय भंडारण और पुनर्प्राप्ति

सेर्साई:

- सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्यूरिटाइजेशन एसेट रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऑफ इंडिया (CERSAI) एक सरकार समर्थित कंपनी है जिसकी स्थापना वित्तीय परिसंपत्तियों और KYC रिकॉर्ड से संबंधित केंद्रीकृत रजिस्ट्रियों को बनाए रखने के लिए की गई है।

स्थापित	2011
प्रशासनिक मंत्रालय	वित्त मंत्रालय
हेडक्वार्टर्स	नई दिल्ली

कार्य

- CKYCRR को बनाए रखता है।
- कई वित्तपोषण और धोखाधड़ी को रोकता है।
- सुरक्षा हित रिकॉर्ड बनाए रखता है।
- वित्तीय पारदर्शिता का समर्थन करता है।

अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी)

- अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से वित्तीय संस्थान वित्तीय सेवाएं प्रदान करने से पहले ग्राहकों की पहचान और पते को सत्यापित करते हैं।

उद्देश्य

मनी लॉन्ड्रिंग को रोकें।
आतंकवादी वित्तपोषण को रोकें।
ग्राहक की पहचान सत्यापित करें।
वित्तीय धोखाधड़ी का पता लगाएं।
वित्तीय अखंडता को मजबूत करें।

धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002:

- धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण से निपटने के लिए भारत का प्रमुख कानून है।

उद्देश्य:

- अवैध धन के शोधन को रोकें।
- अपराध की आय को जब्त करना।
- वित्तीय अखंडता को मजबूत करें।
- अंतरराष्ट्रीय एएमएल मानकों का अनुपालन करें।

मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम (अभिलेखों का रखरखाव) नियम, 2005:

ये नियम निर्धारित करते हैं:

ग्राहक उचित परिश्रम (सीडीडी)।
केवाईसी आवश्यकताएं।
रिकॉर्ड रखरखाव।
रिपोर्टिंग दायित्व।
सीकेवाईसी ढांचे का संचालन।

केवाईसी और सीकेवाईसी के बीच अंतर

केवाईसी	सीकेवाईसी
संस्थान-विशिष्ट	केंद्रीकृत और पुन: प्रयोज्य
बार-बार जमा किए गए दस्तावेज़	एक बार जमा करना
प्रत्येक संस्थान के लिए अलग केवाईसी	एकल सीकेवाईसी आईडी सभी संस्थानों में मान्य है
एकाधिक डेटाबेस	केंद्रीय भंडार (सीकेवाईसीआरआर)

सीकेवाईसी 2.0

- प्रस्तावित सीकेवाईसी 2.0 ढांचे का उद्देश्य भारत के केवाईसी इकोसिस्टम को आधुनिक बनाना है।

प्रमुख विशेषताएं

- केवाईसी डेटा की सहमति-आधारित साझाकरण।
- ग्राहक रिकॉर्ड का वास्तविक समय अद्यतन।
- आत्मविश्वास स्कोर के माध्यम से डेटा की गुणवत्ता में सुधार।
- नियामकों और वित्तीय संस्थानों के बीच बेहतर पारस्परिकता।
- तेज़ डिजिटल ऑनबोर्डिंग।

CKYC का उपयोग करने वाले वित्तीय क्षेत्र के नियामक

क्षेत्र	नियामक
बैकिंग	भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई)
प्रतिभूति बाजार	भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी)
सुरक्षा-कवच	भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI)
पेंशन	पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA)

एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (AML):

- एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) कानूनों, विनियमों और प्रक्रियाओं को संदर्भित करता है जो अपराधियों को अवैध रूप से प्राप्त धन को वैध आय के रूप में छिपाने से रोकने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।

अवयव

- ग्राहक उचित परिश्रम (सीडीडी)।
- केवाईसी सत्यापन।
- संदिग्ध लेनदेन रिपोर्टिंग।
- रिकॉर्ड रखना।
- जोखिम-आधारित निगरानी।

वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF):

- फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) एक अंतर-सरकारी निकाय है जो मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण से निपटने के लिए वैश्विक मानकों को विकसित करता है।

• स्थापित:1989
• राष्ट्रपति: एलिसा डी एंडा माद्राज़ो
• मुख्यालय: पेरिस, फ्रांस
• प्रकृति: अंतर-सरकारी संगठन

कार्य:

- एएमएल/सीएफटी मानक निर्धारित करता है।
- सदस्य देशों का मूल्यांकन करता है।
- वित्तीय अखंडता पर सिफारिशें जारी करता है।

परीक्षा फोकस बिंदु:

• फुल फॉर्म: सेंट्रल नो योर कस्टमर (सीकेवाईसी)।
• विशिष्ट पहचानकर्ता: 14-अंकीय केवाईसी पहचानकर्ता (KIN)।
• रजिस्ट्री: सेंट्रल केवाईसी रिकॉर्ड्स रजिस्ट्री (सीकेवाईसीआरआर)।
• द्वारा अनुरक्षित: CERSAI।
• कानूनी ढांचा: धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 और धन शोधन निवारण (अभिलेखों का रखरखाव) नियम, 2005।
• उद्देश्य: कई वित्तीय संस्थानों के लिए एक बार केवाईसी।
• प्रमुख नियामक: आरबीआई, सेबी, आईआरडीएआई और पीएफआरडीए।
• अंतर्राष्ट्रीय निकाय: वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ)।

वैभव सूर्यवंशी अंतरराष्ट्रीय अर्धशतक बनाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने

- वैभव सूर्यवंशी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अर्धशतक लगाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं।
- उन्होंने 19 गेंदों में अपना पहला अंतरराष्ट्रीय अर्धशतक जड़ा।
- यह उपलब्धि जिम्बाब्वे के हरारे में जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले टी20 आई में आई।
- उन्होंने अंतरराष्ट्रीय अर्धशतक बनाने वाले भारत के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी के रूप में सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया।
- भारत ने जिम्बाब्वे को 7 विकेट से हराकर तीन मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है।

वैभव सूर्यवंशी के बारे में

- वैभव सूर्यवंशी भारत के सबसे होनहार युवा क्रिकेटरों में से एक हैं। बिहार के समस्तीपुर जिले में जन्मे, उन्होंने घरेलू, अंडर -19, आईपीएल और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के माध्यम से तेजी से प्रगति की है।

कैरियर हाइलाइट्स

- अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण करने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय।
- अंतरराष्ट्रीय अर्धशतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी।
- घरेलू क्रिकेट में बिहार का प्रतिनिधित्व किया।
- इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हैं।
- भारत के आईसीसी अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप 2026 अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी):

• स्थापित:1909
• मुख्यालय: दुबई, संयुक्त अरब अमीरात
• पूर्व नाम: इंपीरियल क्रिकेट सम्मेलन
• सदस्य: 108 (पूर्ण सदस्य और सहयोगी सदस्य)
• अध्यक्ष: जय शाह
• CEO: संजोग गुप्ता

- महाप्रबंधक: वसीम खान

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई):

- भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) भारत में क्रिकेट के लिए शासी निकाय है।

- स्थापित:1928
- मुख्यालय: मुंबई
- से संबद्ध: अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी)
- अध्यक्ष: मिथुन मन्हास
- उपाध्यक्ष: राजीव शुक्ला
- सचिव: देवजीत सैकिया
- पुरुष कोच: गौतम गंभीर
- महिला कोच: अमोल मजूमदार

जिम्बाब्वे:

- राजधानी: हरारे
- मुद्रा: जिम्बाब्वे गोल्ड (ZiG)
- राष्ट्रपति: एमर्सन मनांगाग्वा
- महाद्वीप: अफ्रीका

भूगोल:

- पड़ोसी देश: दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना, जाम्बिया, मोजाम्बिक और नामीबिया (कज़ुंगुला सीमा क्षेत्र के माध्यम से)।
- प्रमुख नदी: ज़ाम्बेज़ी नदी।
- प्रसिद्ध झरना: विक्टोरिया फॉल्स (जाम्बिया के साथ साझा)।
- सबसे ऊंची चोटी: माउंट न्यांगानी।

हरारे स्पोर्ट्स क्लब:

- हरारे, जिम्बाब्वे में स्थित है।
- जिम्बाब्वे के प्रमुख अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्थलों में से एक।
- टेस्ट मैच, वनडे, टी20 और आईसीसी टूर्नामेंट की मेजबानी करता है।

भारतीय क्रिकेट में युवा विकास

भारत ने निम्नलिखित के माध्यम से एक मजबूत क्रिकेट प्रतिभा पाइपलाइन विकसित की है:

- आयु-वर्ग क्रिकेट (अंडर-16, अंडर-19)।
- राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी (एनसीए)।
- आईपीएल एक्सपोजर।
- घरेलू टूर्नामेंट जैसे:
- रणजी ट्रॉफी।
- विजय हजारे ट्रॉफी।
- सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी।

राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी (एनसीए)

- स्थान: बेंगलुरु, कर्नाटक
- स्थापित : 2000
- द्वारा नियंत्रित: बीसीसीआई

आईसीसी में वर्तमान में 12 पूर्ण सदस्य देश हैं, जिनमें शामिल हैं:

- भारत
- ऑस्ट्रेलिया
- इंग्लैंड
- दक्षिण अफ्रीका
- पाकिस्तान
- न्यूज़ीलैंड
- श्रीलंका
- बांग्लादेश
- जिम्बाब्वे
- वेस्टइंडीज
- अफ़गानिस्तान
- आयरलैंड

परीक्षा फोकस बिंदु:

- खिलाड़ी: वैभव सूर्यवंशी
- उपलब्धि: अंतरराष्ट्रीय अर्धशतक बनाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी।
- प्रारूप: टी20 अंतर्राष्ट्रीय।
- प्रतिद्वंद्वी: जिम्बाब्वे।
- स्थान: हरारे स्पोर्ट्स क्लब, हरारे।
- आयु: 15 वर्ष।

• शासी निकाय: अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी)।	• गृह राज्य: बिहार।
• भारतीय क्रिकेट शासी निकाय: बीसीसीआई।	
• आईपीएल फ्रेंचाइजी: राजस्थान रॉयल्स।	

लेट्स रिवाइज

❖ किस संगठन ने भारत का पहला स्वदेशी एक्सपेंडेबल टर्बोजेट इंजन विकसित किया? डीआरडीओ का गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट (जीटीआरई)।

❖ डीआरडीओ का कुश किस श्रेणी की मिसाइल से संबंधित है? लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल (LRSAM)

❖ भारत ने हाल ही में किस यूरोपीय देश के साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी, शिक्षा और खेल के क्षेत्र में समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं? रोमानिया।

❖ कौन सी समिति भारत सरकार के सचिवों की नियुक्ति को मंजूरी देती है? मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (एसीसी)।

❖ इंफोसिस के सीईओ और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है और 1 अप्रैल 2027 से पदभार ग्रहण करेंगे? आशीष कुमार दास।

❖ हाल ही में खबरों में आई 'समुद्र प्रदक्षिणा' निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ी हुई है? भारत का पहला त्रि-सेवा सर्व-महिला परिभ्रमण नौकायन अभियान।

❖ किस अमेरिकी कानून के तहत 2026 में भारतीय सामानों पर अतिरिक्त टैरिफ लगाया गया था? अमेरिकी व्यापार अधिनियम, 1974 की धारा 301।

❖ भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद तस्करी और जबरन श्रम पर प्रतिबंध लगाता है? अनुच्छेद 23.

❖ कौन सा अधिनियम भारत में भुगतान प्रणालियों के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है? भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007

❖ कौन सा संगठन केंद्रीय केवाईसी रिकॉर्ड रजिस्ट्री (सीकेवाईसीआरआर) का रखरखाव करता है? सेर्साई।

❖ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अर्धशतक बनाने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बने? वैभव सूर्यवंशी।

The ACHIEVERS IAS ACADEMY

The ACHIEVERS IAS ACADEMY PATNA

Daily NEWS CHRONICLE

IMPORTANCE OF CURRENT AFFAIRS IN UPSC EXAMINATIONS

Current Affairs hold a crucial place in the preparation for the UPSC Civil Services Examination. A comprehensive understanding of recent national and international developments helps aspirants strengthen their General Studies foundation and develop a well-rounded perspective on important issues. Topics such as government policies, schemes, economy, international relations, science and technology, environment, defence, social justice, governance, reports, indices, appointments, awards, and major global events are highly relevant for both the Prelims and Mains examinations. Regular study of current affairs not only enhances factual knowledge but also improves analytical ability, critical thinking, answer-writing skills, and decision-making aptitude. Since UPSC questions often connect contemporary developments with static subjects, consistent preparation of current affairs enables aspirants to understand issues in depth and present balanced, informed, and relevant answers. It also plays an important role in Essay writing, Ethics, and the Personality Test, giving candidates a strong edge throughout the examination process.

CONTACT US

+91 8434931877 achievers_ias_patna PATLIPUTRA GOLAMBAR

ACHIEVERS IAS ACADEMY (UPSC/BPSC) achieversiaspatna@gmail.com

Achievers IAS Academy www.achieversiaspatna.co.in Achievers IAS Academy, PATNA